पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International (25 years, 1983–2008)

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 12, अंक 2/2011

... गरीबों को नकद सब्सिडी

सरकार उर्वरक, मिट्टी के तेल और रसोई गैस जैसी चीजों की कीमतें कम करने के लिए उन पर सब्सिडी देती है, लेकिन सब्सिडी की यह रकम सामान बनाने वाली या उन्हें बेचने वाली कंपनी को दी जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी गरीबों के लिए करोड़ों रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद लक्षित समूह तक उसका पूरा फायदा नहीं पहुंच रहा। इसके मद्देनजर सरकार ने बजट में अगले साल से रसोई गैस, कैरोसिन और उर्वरकों की बिक्री पर सब्सिडी खत्म करने की योजना बनाई है। इसके बजाय सरकार सब्सिडी के पेटे गरीबों को सीधे नकदी भुगतान करेगी। नकद सब्सिडी की पायलट परियोजना सात राज्यों तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उड़ीसा में शुरू की जाएगी।

हाल ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के चेयरमेन नंदन नीलकेणी ने सब्सिडी की प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए गरीबों को सीधे नकद सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखते हुए इस बारे में 70 पृष्ठ की अंतरिम रिपोर्ट वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को सौंप दी है। सरकार द्वारा स्थापित इस प्राधिकरण के सुझावों में गरीब परिवारों को अब मिट्टी का तेल, रसोई गैस और उर्वरक के लिए मिलने वाली नकद सब्सिडी सीधे बैकों, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए दिया जाना है।

ऐसे में नकद सब्सिडी एक अच्छी शुरुआत मानी जा रही है। इस व्यवस्था को सीधे विशेष पहचान पत्र यानि यूआईडी से जोड़ने और गरीबों को यह कार्ड मिल जाने से उसको सब्सिडी की एवज में मिलने वाली नकद राशि को कोई छीन नहीं सकेगा।। इससे सब्सिडी के वितरण पर नजर रखना आसान हो जाएगा। सरकार के पास भी यह हिसाब रह सकेगा कि किस व्यक्ति को कितनी सब्सिडी दी गई। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा।

इस अंक में...

- केबिनेट बैठकों में नहीं आते कई मंत्री 4
- भ्रष्टाचार से हताश हैं भारतीय 5
- गरीब परिवारों को मिलेंगे मकान 7
- पवन ऊर्जा विकास में राज्य अव्वल 8
- अगली पीढ़ी के लिए हो सकता है जल संकट 9

विकलांगों के मुद्दों पर संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु कार्ययोजनाएं

'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा साइटसेवर्स के सहयोग से विकलांगता को मुख्यधारा से जोड़ने की परियोजना के तहत मुख्यधारा के मुद्दों पर धरातल स्तर पर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं, लॉ व सोशल वर्क के महाविद्यालयों के साथ निर्धारित उद्देश्यों युक्त एक दिवसीय संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। ये संवदेनशील कार्यशालाएं राजस्थान के विभिन्न जिलों में विकलांगता को मुख्य धारा में जोड़ने की अपने आप में एक पहली कोशिश है, जिनमें चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि व कर्मचारी, जिन्हें इस विषय पर पहले कोई औपचारिक प्रशिक्षण या जानकारी नहीं दी गई थी, शामिल थे।

अब तक लगभग 16 कार्यशालाओं का आयोजन राजस्थान के विभिन्न जिलों यथा जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर जिलों में किया जा चुका है। इन कार्यशालाओं में अनुमानित कुल 700 व्यक्तियों ने, जो कि धरातल स्तर पर विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, ने उत्साह से भाग लिया। कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को विकलांगता के मुद्दों, कानूनों व मॉडलों, विकलांगता को मुख्यधारा से जोड़ने में आ रही बाधाओं व कुछ अन्य सम्बन्धित विषयों पर विषय विशेषज्ञ प्रसन्ना कुमार पिंचा, विशेष अभिसंचेता, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा परियोजना अधिकारी मधुसूदन शर्मा द्वारा जानकारी प्रदान की गई।

एक दिवसीय हर कार्यशाला को मुख्यत: दो चरणों में बांटा गया था। प्रथम चरण में, विकलांगता के सैद्धांतिक मुद्दों पर चर्चा की गई तथा दूसरे चरण में एक समूह कार्य व कार्य योजना का निर्माण करने की गतिविधि की गई। इसमें मुख्यत: कार्ययोजना हेतु विचारणीय मुद्दों तथा विकलांग व्यक्तियों को संस्था से जोड़ने हेतु भावी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

समूह चर्चा में सामने आया कि संस्थाओं को विकलांगता को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु संस्था स्तर पर 'द्विकोणीय कार्ययोजना' अपनाने की आवश्यकता है जिसके तहत संस्थाओं को अपने स्तर पर भी कुछ विकलांग विशेष कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। संस्था के उपलब्ध संसाधनों का कुछ प्रतिशत इस हेतु आरक्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य कार्यक्रमों में भी विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकार सम्मत लाभ दिलवाने हेतु पहल करनी चाहिए। अंत में समूह ने यह भी सुझाया कि संस्थाओं के प्रबन्धन में भी कुल विकलांग व्यक्तियों को जगह दी जानी चाहिए जिससे कि उनकी प्राथमिकताओं को भी सर्वोपरी रखा जा सके एवं उनको मुख्यधारा में जोड़ने के प्रयास निरंतर चलते रहें।

'अन्सा' परियोजना के तहत सहयोगी संस्थाओं का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन

'अन्सा' द्वारा समर्थित परियोजना 'कट्स कैग' के तहत पूरे राजस्थान में सुशासन विषय पर स्वयंसेवी संस्थाओं का एक नेटवर्क बनाया गया है। उक्त परियोजना की भागीदार सहयोगी संस्थाओं का राजस्थान सहकारी शिक्षा संस्थान (राईसेम) जयपुर में 18 एवं 19 अप्रेल को दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को समुदाय अंक पत्र पर प्रशिक्षित किया गया।

परियोजना के तहत नरेगा में समुदाय अंक पत्र के क्रियान्वयन की रणनीति पर चर्चा की गई व समुदाय अंक पत्र का दोहरान किया गया। कट्स के ओम प्रकाश आर्य व अमर दीप सिंह ने भागीदारों को नरेगा से सम्बन्धित मूलभूत बातों एवं समुदाय अंक पत्र के प्रत्येक चरणों की जानकारी दी, जो कि परियोजना संचालन में सहायक होगी। भागीदारों को 'सूचना का अधिकार' के बारे में भी संवेदनशील किया गया , जो कि सामाजिक जवाबदेहिता का एक मुख्य औजारहै। रणधीर सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत बुढ़ानिया, झुन्झुनूं ने भागीदारों से चर्चा की और उन्हें 'नरेगा' के विविध तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने योजना के क्रियान्वय में ग्राम पंचायत की भूमिका की भी जानकारी दी गई। कट्स निदेशक जॉर्ज चेरियन ने सुशासन एवं व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में विचार व्यक्त किए व घन्यवाद प्रस्ताव पारित किया।

जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन

जैसा कि विदित है भारत सरकार के उपभोक्ता कल्याण कोष के सौजन्य से राज्य के 12 चयनित जिलों में कट्स द्वारा ग्रेनिर्का परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजना के तहत 3 मई 2011 से 11 जून 2011 तक चयनित जिलों में 23 जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनसंवाद के इन कार्यक्रमों में स्थानीय प्रशासन के उच्चाधिकारियों एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में 1275 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अधिकांश महिलाएं और युवा वर्ग के लोग थे।

कार्यक्रमों के दौरान आमंत्रित मुख्य अतिथियों, विषय विशेषज्ञों एवं कानूनी सलाहकारों ने प्रतिभागियों को उपभोक्ता अधिकारों, उनके कर्तव्यों, जिला उपभोक्ता मंच में पीड़ित उपभोक्ता द्वारा परिवाद दर्ज कराने की प्रक्रिया, उपभोक्ताओं से संबंधित विभागों यथा रसद विभाग, बाट व माप विभाग, मानक संस्था और खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ-साथ वित्तीय सुविधाओं और उनसे संबधित विभिन्न उपभोक्ता समस्याओं की जानकारी दी।

इन कार्यक्रमों के आयोजन का मूल मकसद राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर, उपभोक्ता आंदोलन को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी उपभोक्ताओं ने बिजली, दूरसंचार, खाद, बीज और राशन से सम्बन्धित अनेक मुद्दे प्रमुखता से उठाए, जिनका विषय विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। स्थानीय प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों व प्रतिभागी उपभोक्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रमों को काफी उपयोगी बताया। उनका कहना था कि उपभोक्तावाद के दौर में इस प्रकार के कार्यक्रमों से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी बल्कि कालाबाजारी और बेईमानी पर अंकुश भी लगेगा। कुछ पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीण स्तर पर ऐसे कार्यक्रमों को एक अभियान के रूप में आयोजित करने की मंशा व्यक्त की।

'ग्राम गदर' पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा

ग्रामीण पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 2002 से आरम्भ 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार प्रति वर्ष 13 अप्रेल के दिन घोषित किए जाते हैं। ये पुरस्कार उन श्रेष्ठ पत्रकारों को दिये जाते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जनहित के मामलों को असरदार तरीके से उठाया है। ये पत्रकार चाहे स्वतन्त्र रूप से पत्रकारिता करते हों, या फिर किसी समाचार पत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2010 में उल्लेखनीय लेखन प्रकाशित करने वाले पत्रकारों से 'भ्रष्टाचार' विषय पर प्रविष्ठियां आमन्त्रित की गई थीं। प्राप्त प्रविष्ठियों में से श्रेष्ठ चयन के लिए ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा की अगुवाई में निर्णायक मंडल का गठन किया गया। निर्णायक मंडल द्वारा आम सहमति से भीलवाड़ा जिले के स्वतंत्र पत्रकार लक्ष्मी लाल (लखन सालवी) को वर्ष 2010 के लिए 'ग्राम गदर' ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। श्री सालवी को दस हजार रुपए का नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। । पुरस्कार का वितरण बाद में उचित समय पर किया जाएगा।

लखन सालवी भीलवाड़ा जिले के मूल निवासी हैं तथा दैनिक भास्कर, निराला राष्ट्रध्वज, विविधा फीचर्स, तथ्य भारती, डायमंड इंडिया आदि अनेक छोटे बड़े पत्र-पत्रिकाओं के लिए अपने लेख लिखते हैं , जो कि जनहित के मुद्दों से सीधे जुड़े हुए होते हैं।

कानून तो है पर जब्त नहीं होती संपत्ति

भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए एक भी अफसर-कर्मचारी की संपत्ति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज तक जब्त नहीं की है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कानून नहीं है, क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1944 के तहत भ्रष्ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्त करने का अनुसंधान एजेंसी को स्पष्ट अधिकार है। ब्यूरो अधिकारी इस कानून के तहत संपत्ति जब्ती की कठिन प्रक्रिया की आड़ में कोई मामला आज तक कोर्ट में नहीं ले गए।

विभाग के ही कुछ अधिकारियों का मानना है कि संपत्ति जब्त करने का यह कानून भ्रष्टाचारियों का मनोबल तोड़ने में प्रभावी हथियार साबित हो सकता है। यदि प्रक्रिया कठिन है तो इसके तहत कार्रवाई करते हुए सरकार से आसान कानून बनाने की शिफारिश की जानी चाहिए। *(दै.भा., 10.05.11)*

बीपीएल कार्ड के बदले दे रहे हैं कर्ज

औसत आय से कम आय वालों को सरकार गरीब मानते हुए 'बीपीएल कार्ड' जारी करती है। लेकिन उनके इस कार्ड का लाभ कोई और ही उठा रहा होता है। हाल ही कोटा जिले में ऐसे मामले सामने आए हैं। एक सत्तर वर्षीय वृद्धा महिला का बीपीएल कार्ड और किसी ने नहीं बल्कि उसके शराबी बेटे ने शराब के रुपयों के खातिर दौ सौ रुपए में गिरवी रख दिया। बताया गया कि महिला का कार्ड अब एक माह का और राशन उठाने के बाद लौटाया जाएगा।

शहर के वार्ड 50 स्थित राधाविलास पाटनपौल में ऐसे और भी कई गरीब परिवार हैं जिनके बीपीएल और राशनकार्ड गिरवी हैं। इस वार्ड के कांग्रेस के उपाध्यक्ष अकबर बताते हैं कि राशन विक्रेता को उसी व्यक्ति को राशन देना चाहिए जिसका कार्ड हो। लेकिन यह सब राशन विक्रेता की शह पर होता है। *(रा.प., 31.05.11)*

बह रही है उल्टी गंगा

राज्य का कृषि विपणन बोर्ड आमदनी वाले प्रस्तावों को ही ठुकरा रहा है। इसी आमदनी में से बोर्ड का खर्चा चलता है। बोर्ड ने पिछले वर्ष 250 करोड़ रुपए के ठेके ठुकराए थे। इस वित्तीय वर्ष की स्थिति यह है कि 150 करोड़ रुपए के मंडी यार्डों के विकास के ठेके में से अब तक करीब 120 करोड़ रुपए के काम ही हो सके हैं। इस तरह दोनों वर्षों में मिला कर कुल 280 करोड़ रुपए के ठेके बोर्ड ठुकरा चुका है। विकास कार्यों के काम ठुकराने से मण्डियों में होने वाले दो दर्जन से ज्यादा कार्यों पर विराम लग गया है। *(रा.प., 05.04.11)*

अटकी पड़ी है करोड़ों की टैक्स वसूली

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बीते पांच सालों के दौरान 2 लाख 63 हजार करोड़ से भी ज्यादा का टैक्स नहीं वसूला जा सका। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की हाल ही तैयार की गई रिपोर्ट इस तथ्य को उजागर करती है। सीएजी ने इसके लिए बेकार हो चुके कर वसूली तंत्र और अधिकारियों की अक्षमता को जिम्मेदार ठहराया है।

सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि टैक्स डिमांड 2005-06 के दौरान 95,387 करोड़ रुपए थी, वह 2010-11 में बढ़कर 2,63,260 करोड़ रुपए हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान कर विभाग में टैक्स रिकवरी अफसर (टीआरओ) की संख्या विभाग के लिए तय अधिकारियों से कम रही है जिसका कारण नई नियुक्ति नहीं किया जाना है। रिपोर्ट में आकलन अधिकारी व टीआरओ के बीच रहे सामंजस्य की कमी को भी रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट अभी संसद में पेश की जानी है। *(दै.भा., 16.05.11)*

डकार जाते हैं गरीबों का राशन

खाद्य मंत्री बाबूलाल नागर ने प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली में भारी गड़बड़ी होने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि राशन डीलर साल में तीन महीने का राशन खुद डकार जाते हैं और जनता को सिर्फ नौ महीने का राशन मिल पाता है। इस गड़बड़ी में राशन डीलरों के साथ-साथ कुछ सरकारी नुमाइन्दे भी शामिल होते हैं।

उन्होंने बताया कि राशन वितरण को बेहतर और गड़बड़ी रहित बनाने के लिए हाल ही जिला और तहसील स्तर पर सतर्कता समिति और आंवटन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इन समितियों में स्थानीय नागरिकों को भी शामिल किया गया है। इन्हें कभी भी राशन की दुकानों के निरीक्षण का अधिकार होगा। समिति सदस्य सरकारी नुमाइन्दों व डीलरों के खिलाफ पुख्ता सबूत होने पर कानूनी कार्रवाई तक कर सकते हैं। *(रा.प., 09.04.11)*

उद्योग लगाने के नाम पर ली सस्ती जमीन

विकास के नाम पर एक ओर तो सरकार किसानों की उपजाऊ जमीन ले रही है, दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्रों में जमीनों की ट्रेडिंग करवा रही है। पूरे प्रदेश में 7400 से ज्यादा ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में रीको से जमीनें तो ले ली, लेकिन आज तक कोई उद्योग नहीं लगाया।

रीको रिकॉर्ड के अनुसार इन्हें जमीन आवंटित किए एक दशक से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन वह खाली पड़ी है। इनमें 4000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अटकी हुई है। यदि इन पर उद्योग लगते और एक इंडस्ट्री से औसतन 200 लोगों को भी रोजगार मिलता तो करीब 1.50 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलते। रीको के भू-आवंटन एवं संपत्ति निस्तारण नियम कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र विकसित घोषित होने के 3 साल में उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए लेकिन इन नियमों की पालना नहीं हो रही। नियमानुसार अब तक तो आवंटन रद्द हो जाना चाहिए था। *(दै.भा., 25.06.11)*

बेहिसाब घोटाला, नहीं हुई कार्रवाई

कृषि विभाग की अनुदानित योजनाओं में एक करोड़ से भी अधिक का घोटाला उजागर होने के बावजूद शासन और प्रशासन ठोस कार्रवाई करने से हिचक रहा है। करौली जिले में वर्ष 2008 से 2010 के दौरान विभाग ने किसानों के लिए फार्म पौण्ड, सिंचाई फव्वारा, पाइप लाइन समेत कई अनुदानित योजनाओं में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ।

अकेले फार्म पौण्ड योजना में सवा करोड़ से अधिक का अनुदान जारी किया। जिले में 450 फार्म पौण्ड बनाने का लक्ष्य तय किया, जबकि मुश्किल से 100 फार्म पौण्ड ही बने, बाकी 350 फार्म पौण्ड अधिकारियों ने मिलीभगत कर कागजों में तैयार बता कर किसानों के नाम अनुदान जारी कर दिया। फव्वारा योजना में भी गलत बिल पेश करने की बात सामने आने पर मामलों की जांच हुई। जांच के बाद एक बार फिर से जांच हुई, जांच में बेहिसाब घोटाला सामने आया लेकिन किसी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। *(रा.प., 19.04.11)*

सरकारी गेहूं फिर खुले में

इस बार फिर राज्य में समर्थन मूल्य पर खरीदा हजारों टन सरकारी गेहूं खुले में पड़ा है। एफसीआई और सहयोगी एजेंसियों के गोदाम ठसाठस भर चुके हैं। कई जगह गेहूं खुले में तिरपाल से ढक कर रखना पड़ रहा है जबकि राज्य में मानसून पूर्व की वर्षा शुरू हो चुकी है ।

अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर सहित और भी कई जिलों में गेहूं खुले में पड़ा है। कई जगह गेहूं भीगने भी लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में यह गेहूं आम आदमी तक सुरक्षित पहुंच भी पाएगा या नहीं, यह विश्वास कर पाना मुश्किल है। यदि समय रहते इसे रखने के इंतजाम नहीं किए गए तो खुले में पड़ा गेहूं सड़ भी सकता है। *(रा.प., 14.06.11)*

वाणिज्यिक कर वसूली बनी गल फांस

वाणिज्यिक कर विभाग के लिए कई साल से व्यापारियों पर बकाया करीब पांच हजार करोड़ रुपए की वसूली सिरदर्द साबित हो रही है। हाल ही चलाए गए विशेष वसूली अभियान के बावजूद विभाग अब तक मात्र 575 करोड़ रुपए ही वसूल सका है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभिन्न कारणों के चलते कई सालों से यह वसूली नहीं की जा सकी। इससे यह राशि लगातार हर साल जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से वसूली नहीं हो पा रही है।

वर्तमान में विभाग की यह बकाया कर राशि 4960 करोड़ रुपए है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय स्थगन आदेश के कारण बड़ी तादाद में मामले लम्बित हैं। जब तक न्यायालय से मामले का निपटारा नहीं होता बड़ी राशि फंसी रहने की उम्मीद है। कई फर्मों के दिवालिया होने, बीमार यूनिट बनने, मालिकों के लापता होने आदि ऐसे कारण है जिससे इतनी बड़ी रकम नहीं वसूली जा सकी। *(रा.प., 29.06.11)*

किसानों को करोड़ों का फर्जी मुआवजा

बारां जिले के छीपाबड़ौद तहसील में ल्हासी मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आए किसानों को दिए गए मुआवजे में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि जमीन प्रस्तावित परियोजना के डूब क्षेत्र में नहीं आने पर भी कई रसूखदार किसानों को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का मुआवजा दिलवा दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर, विभाग ने भी ब्यूरो द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड जांच के लिए उपलब्ध करवा दिया है। *(रा.प., 19.06.11)*

केबिनेट बैठकों में नहीं आते कई मंत्री

यूपीए सरकार के दो साल पूरे हो चुके हैं। 2010-11 में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर केबिनेट की 48 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इतने बड़े मंत्रीमंडल में सिर्फ 8 मंत्री ही ऐसे हैं जिनकी उपस्थिति साठ फीसदी से अधिक है। यानि हाजरी के मामले में ये प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण माने जा सकते हैं। बैठकों में सर्वाधिक उपस्थिति वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की है।

कैबिनेट में मंत्रियों की मौजूदगी की यह जानकारी सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता एससी अग्रवाल द्वारा मांगी गई थी।

केबिनेट की बैठकों में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है और अनेक निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में ज्यादातर यूपीए मंत्रियों का गैरहाजिर रहना उनकी जवाबदेही पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। *(दै.भा., 26.06.11)*

कब भरेंगे विद्युत निगम में खाली पद

बिजली चोरी के बढ़ते ग्राफ के बीच अगर राजस्थान डिस्कॉम की सतर्कता शाखा पर नजर डालें, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। प्रदेश के तीनों डिस्कॉम में जांच अधिकारियों के करीब 45 फीसदी पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं।

इससे न सिर्फ एक हजार से भी अधिक दर्ज प्रकरणों की जांच की रफ्तार धीमी चल रही है, बल्कि कठोर कार्रवाई नहीं होने से विद्युत चोरों के हौंसले भी बुलन्द होते जा रहे हैं।

हालात यह है कि पहले तो बिजली चोरी के मामले सामने आते ही नहीं और अगर आते हैं तो जांच की धीमी प्रक्रिया में अटक जाते हैं। पिछले साल जयपुर डिस्कॉम में 3.56 फीसदी, अजमेर डिस्कॉम में 2.84 फीसदी और जोधपुर डिस्कॉम में 5.55 फीसदी प्रकरण पैंडेंसी में हैं। *(रा.प., 19.06.11)*

वार्षिक योजना-नहीं हुई पूरी राशि खर्च

पिछले साल ऐतिहासिक वार्षिक योजना बनाने के बावजूद बिजली, पानी, सड़क व शहरी विकास जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजना राशि पूरी तरह खर्च नहीं हुई। हालात यह बने कि राज्य सरकार वार्षिक योजना के अनुसार 3000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई।

पिछले साल 24,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना स्वीकृत हुई थी लेकिन उसके मुकाबले करीब 21,094 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। सरकार बिजली परियोजनाओं के लिए कोयले के ब्लॉक आवंटित नहीं होने को इसके लिए प्रमुख कारण गिना रही है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार पानी, सड़क व शहरी विकास में भी पूरी योजना राशि खर्च करने में सुस्त रही है। *(रा.प., 09.05.11)*

गरीबों के गेहूं की कालाबाजारी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत मिली कि अलवर जिले के खेड़ली गंज कस्बे में राशन डीलर रामावतार क्षेत्र के अन्य राशन डीलरों से एपीएल, बीपीएल, अन्नपूर्णा व अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले गेहूं, चीनी, केरोसिन व आटे को खरीद कर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता है।

ग्रामीणों से मिली इस शिकायत पर राशन डीलर रामावतार खंडेलवाल के गोदाम पर ब्यूरो ने छापा मारा। गोदाम से ब्यूरो अधिकारियों ने राशन का करीब ढाई हजार क्विंटल गेहूं जब्त किया। जांच में सामने आया कि रामावतार द्वारा आसपास के राशन डीलरों से मिलीभगत कर यह गेहूं कालाबाजारी के लिए जमा किया गया था। *(दै.भा., 03.05.11)*

स्वास्थ्य विभाग में नौ करोड़ का घोटाला

अलवर के दिनेश जैन की शिकायत पर वित्त विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, अलवर की 2003-04 से 2007-08 तक की विशेष ऑडिट कराई थी, जिसमें नौ करोड़ रुपए की वित्तीय गड़बड़िया सामने आई थीं।

इस मामले पर पिछले एक साल से पर्दा डाला जा रहा था। राजस्थान पत्रिका के माध्यम से पांचवा स्तम्भ के पिछले अंक में भी 'खुली स्वास्थ्य अभियानों की पोल' शीर्षक के तहत मामले को प्रकाशित किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इस पर कार्रवाई करते हुए 21 अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। इनमें विभाग के एक संयुक्त निदेशक सात पूर्व सीएमएचओ, लेखाधिकारी और चिकित्सक शामिल हैं। *(रा.प., 21.04.11)*

भ्रष्टाचार में राजस्थान भी अव्वल

महाराष्ट्र व राजस्थान जैसे बड़े राज्य भ्रष्टाचार की सीढ़ी में शीर्ष पायदान पर खड़े हैं। इन राज्यों में दर्ज भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या के मुकाबले दोषियों को सजा दिए जाने का प्रतिशत भी काफी कम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कुल 4566 मामले दर्ज किए गए। और उनमें से केवल 27 फीसदी मामलों में ही आरोपियों पर दोष साबित हो पाए। इन मामलों में राज्य में नौ करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई।

इसी प्रकार राजस्थान में दर्ज 3770 मामलों में से 33 फीसदी मामलों का ही निपटारा हो पाया। वर्ष 2000 में जहां देश में कुल 2943 मामले दर्ज हुए वहीं 2009 में 3683 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए। इन मामलों में केवल 60 फीसदी पर ही दोष साबित हुए और साठ करोड़ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई। *(रा.प. 25.04.11)*

किताब में आया 'पुलिस सबसे भ्रष्ट'

एक गरीब रिक्शावाला हो या धार्मिक करोड़पति, पुलिस सबसे रिश्वत लेती है। वास्तव में अपराध फलते फूलते ही पुलिस के सहयोग से है। कोई भी कानून तोड़ने पर पुलिस को पैसा देकर छूटना आसान है। राज्य की पुलिस पर यह किसी नेता, लेखक या विचारक की टिप्पणी नहीं बल्कि उस पाठ का हिस्सा है जो कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है।

श्री वर्द्धमान कोटा खुला विश्वविद्यालय के स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही पुस्तक 'भारत की सामाजिक समस्या' के एक अध्याय में यह बात कही गई है। इस किताब में स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कटाक्ष किया गया है। जिसमें राजनेता, अफसर आदि को निशाना बनाते हुए उनके नैतिक स्तर में सुधार की जरूरत बताई गई है। *(दै.भा., 17.05.11)*

इतने जीरो तो जीवन में नहीं देखे

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में आयकर विभाग की जांच रिपोर्ट में दर्ज राशि में जीरो की संख्या देख कर सुप्रीम कोर्ट चकित है। कोर्ट ने इस इतनी बड़ी राशि को दिमाग हिला देने वाला बताया। कोर्ट ने जांच की धीमी गति के लिए आयकर विभाग से नाराजगी जताई और कहा-उन्हें जांच के स्तर से नहीं परिणाम से मतलब है।

मामले में आयकर विभाग की पहली रिपोर्ट को देखते हुए जस्टिस जीएस सिंघवी और जस्टिस एके गांगुली की बेंच ने कहा 'हमने इतने जीरो अपनी जिंदगी में नहीं देखे।' बैंच ने कहा 'आयकर विभाग को तेजी दिखानी चाहिए, यह आयकर चोरी का सामान्य मामला नहीं है। बैंच ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नामक एनजीओ व अन्य याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि घोटाले में दोषी पाए जाने पर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिर चाहे वह कितना ही अमीर हैसियत वाला और शक्ति शाली क्यों न हो। *(दै.भा., 06.05.11)*

भ्रष्टाचार से देश की छवि धूमिल

आईटी कम्पनी इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल हुई है। मनमोहन सिंह जैसा ईमानदार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी एक असाधारण व्यक्तित्व वाली महिला है, लेकिन लोकपाल बिल पर इनके रवैये से मैं खुश नहीं हूं।

उन्होंने कहा कि यह मेरी राय या शब्द नहीं है बल्कि ये वो शब्द हैं जो मुझे विदेशी लोगों से मुलाकात के दौरान पता चला है। उनका कहना है कि उनसे विदेशों में हर माह 30 से 40 लोग मिलते हैं इनमें से हर तीसरा व्यक्ति मुझसे भारत में बढ़ रहे भ्रष्टाचार की बात करता है। *(दै.भा., 18.06.11)*

हम हैं घोटालों से शर्मसार

ब्रिटेन में रहने वाले और भारतीय मूल के उद्योगपति स्वराज पॉल ने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा बताते हुए कहा है कि हाल ही में जो घोटाले सामने आए हैं वे किसी भी भारतीय को गौरवान्वित नहीं करते। भ्रष्टाचार की भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय शर्म का मुद्दा है। सबसे बड़ी कठिनाई भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने की है।

उन्होंने कहा यदि इसके लिए कानून का पालन करना है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि जो लोग दंड के भागीदार है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कार्पोरेट जगत के लोगों से खुद से और ईमानदारी बरतने का संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में हमेशा लेने और देने वाला होता है। यह एक तरफा नहीं हो सकता। *(रा.प., 01.06.11)*

न दे रिश्वत, मांगे तो दे सूचना

गृह विभाग के उप सचिव के भ्रष्टाचार मामले में पकड़ में आने के बाद हरकत में आए गृह विभाग ने अपने यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू की है।

गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्य सतर्कता आयुक्त की ओर से राजस्थान सचिवालय में आमजन की पहुंच वाले विभिन्न स्थानों पर पट्टिकाएं लगाई गई हैं जिसमें कहा गया है कि 'रिश्वत नहीं दें, कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है या भ्रष्टाचार की किसी को जानकारी है या आप स्वयं पीड़ित है तो शिकायत करें।' यह पट्टिकाएं हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लगाई गई हैं।

यहां करें शिकायत

टेलीफोन नम्बर- 0141-2227112

फैक्स नम्बर- 0141-2227778

वेबसाइट-www.home.rajasthan.gov.in

(रा.प. 03.06.11)

भ्रष्टाचार से हताश हैं भारतीय

देश में व्याप्त भ्रष्टाचार से लगभग सभी भारतीय हताश हैं। देश में भ्रष्टाचार की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अमरीकी सर्वेक्षण एजेंसी 'गैलप' के अनुसार 2010 में करीब आधे लोगों ने माना कि पांच साल पहले की तुलना में भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है जब कि 27 फीसदी लोगों ने इसे समान ही बताया है।

जारी सर्वेक्षण के अनुसार, भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की लड़ाई को मिले व्यापक जनसमर्थन व भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनों से जाहिर होता है कि भारतीयों ने मान लिया है कि भ्रष्टाचार की समस्या समाज में गहराई से पैठ कर गई है। सरकार भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। सर्वेक्षण में 6000 लोगों को शामिल किया गया। *(रा.प.एवं न.नु., 18.05.11)*

भ्रष्टाचार के शर्मनाक आंकड़े

- *78 फीसदी भारतीयों ने माना सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त*
- *71 फीसदी ने कहा व्यापार में भी भ्रष्टाचार*
- *65 फीसदी बेरोजगारों को देनी पड़ी घूस*
- *पांच में से एक व्यक्ति ने कहा कि बीते एक साल में उन्हें देनी पड़ी रिश्वत*

अंजाम तक नहीं पहुंचते घूसखोर

जनता की सजगता भले ही भ्रष्टाचार, पद दुरुपयोग और भ्रष्ट तरीकों से आय से अधिक सम्पत्ति जुटाने में लिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को पकड़वा रही हो, लेकिन अनुसंधान में खामी, प्रभावी पैरवी का अभाव और गवाहों के बयानों से मुकरने के चलते अधिकांश प्रकरणों में आरोपियों को सजा नहीं मिल पाती। पिछले साढ़े पांच सालों में महज 210 मुजरिमों को ही सजा मिली, 458 प्रकरणों में आरोपी बरी हो गए। सजा का प्रतिशत कम होने से जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अनुसंधान प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग रहे हैं, वहीं उन लोगों में निराशा है जिन्होंने दुश्मनी मोल लेकर रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़वाया हैं। *(रा.प., 30.06.11)*

कब और कितनी सजा

वर्ष	निस्तारित प्रकरण	सजा	बरी
2006	181	44	137
2007	157	56	101
2008	124	52	72
2009	76	23	53
2010	65	11	54
31 मई, 2011	65	24	41

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
बाड़मेर	काना राम	अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी, सिवाना	20,000	*दै.भा. एवं रा.प., 04.05.11*
जयपुर	अम्बिका दास कौशिक हरीश चन्द	एसीटीओ, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर कनिष्ठ लिपिक, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर	2,000	*रा.प. एवं दै.भा, 05.05.11*
उदयपुर	असलम परवेज	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, जावरमाइंस	1,00,000	*दै.भा. एवं रा.प., 05.05.11*
जयपुर	अनिल पालीवाल गौरी शंकर सोलंकी	उपशासन सचिव, गृह विभाग कनिष्ठ लिपिक, गृह विभाग	60,000	*रा.प. एवं दै.भा., 12.05.11*
टोंक	दीनदयाल बैरवा	वनपाल, वन विभाग कार्यालय, मालपुरा	4,000	*रा.प., 17.05.11*
श्रीगंगानगर	सुन्दर लाल आहूजा	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर	5,000	*रा.प., 17.05.11*
ब्यावर	रमेश भट्ट पी.के.गुप्ता	फील्ड ऑफीसर, भारतीय स्टेट बैंक सांयकालीन मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक सायंकालीन शाखा	1,500	*रा.प. एवं दै.भा., 19.05.11*
अजमेर	सुवालाल जाट	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	3,000	*रा.प., 19.05.11*
उदयपुर	जी.कृष्णा राव	प्राचार्य, नवोदय सीनियर सैकण्डरी विद्यालय	5,000	*रा.प., 20.05.11*
जयपुर	नरेन्द्र चन्द्र सिंघवी	एक्सईएन, सार्वजनिक निर्माण विभाग	4,000	*दै.भा., 25.05.11*
चित्तौड़गढ़	सोहन बरड़वा चन्द्र सिंह कोठारी	प्रबंध निदेशक, चित्तौड़गढ़- प्रतापगढ़ डेयरी स्टोरकीपर, चित्तौड़गढ़- प्रतापगढ़ डेयरी	15,000	*रा.प., 26.05.11*
चूरू	इन्द्रमोहन गुप्ता	वरिष्ठ लेखाधिकारी आडिट, केन्द्रीय विद्यालय	10,000	*रा.प., 03.06.11*
बारां	घासीलाल	कांस्टेबल, सदर थाना, बारां	2,000	*रा.प., 03.06.11*
श्रीगंगानगर	हरीश शर्मा	कनिष्ठ अभियंता, जल संसाधन विभाग	40,000	*रा.प. एवं दै.भा., 04.06.11*
बीकानेर	हरपाल सिंह	सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम	9,000	*रा.प. एवं दै.भा., 04.06.11*
जयपुर	गोपाल लाल वर्मा	प्रबंधक, रोडवेज डीलक्स आगार पानीपेच	5,000	*दै.भा., 08.06.11*
जयपुर	रामधन चौधरी अरविन्द शर्मा	थाना प्रभारी, करणी विहार थाना, जयपुर दलाल जिसके जरिये रिश्वत ली गई	15,000	*दै.भा. एवं रा.प., 08.06.11*
जयपुर	रमेश परिहार	पटवारी, सांगानेर तहसील, जयपुर	10,000	*दै.भा. एवं रा.प., 10.06.11*
जयपुर	रामचन्द्र उर्फ मोती	परिवहन निरीक्षक आलम खां का निजी गार्ड	12,000	*रा.प. एवं दै.भा., 11.06.11*
अजमेर	महेश पारीक	पटवारी, कालानाडा हल्का, किशनगढ़	5,000	*रा.प., 17.06.11*
कोटा	डॉ.राकेश शर्मा	सहा.आचार्य, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय	5,000	*रा.प. एवं दै.भा., 25.06.11*
झालावाड़	सुधीर सिंह	सहा. प्रबन्धक,सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया,खानपुर	5,000	*रा.प., 26.06.11*
सीकर	गुलजारी लाल	पटवारी, दिवराला, सीकर	8,000	*रा.प., 29.06.11*

राज्य को मिला पहला पुरस्कार

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय पंचायत दिवस के भव्य समारोह में राजस्थान को पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा नवाचार अपनाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए का पहला पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्य के पंचायतीराज मंत्री भरत सिंह को यह पुरस्कार प्रदान किया।

समारोह में अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अरड़का को भी दस लाख रुपए का राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार प्रदान किया गया। अरड़का की सरपंच रईसा खातून होशियारा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। समारोह में राज्य के 64 पंचायत प्रतिनिधियों सहित देशभर के करीब एक हजार पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। *(रा.प. एवं दै.भा., 25.04.2011)*

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पढ़ाई

अजमेर जिले के 247 ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के बच्चे कम्प्यूटर से उपयोगी जानकारी ले सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट सुविधा मिलने से इन बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। दूर बैठे विषय विशेषज्ञ अध्यापक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पढ़ा सकेंगे।

केन्द्रीय संचार एवं सूचना प्रौधोगिकी राज्यमंत्री सचिन पायलट की पहल पर हाल ही इस योजना की शुरुआत की गई है।

योजना के तहत स्कूलों में कम्प्यूटर लैब स्थापित करने का काम शुरू हो गया है। हर लैब में पांच कम्प्यूटर, जनरेटर और बड़ी स्क्रीन का एलसीडी व इंटरनेट होंगे। इसके लिए हर स्कूल को 10-10 लाख रुपए की राशि दी गई है। केन्द्र सरकार इस योजना पर कुल 24 करोड़ 72 लाख रुपए खर्च करेगी। योजना के सफल होने पर प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी योजना को लागू किया जाएगा।

(रा.प., 30.04.11)

बुजुर्गों को रेल यात्रा में छूट बढ़ी

रेलवे बजट में की गई घोषणा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को पिछले महीने से रेल किराए में छूट मिलना शुरू हो गया है। अब 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 30 की बजाय 40 प्रतिशत रियायत मिलेगी।

वरिष्ठ महिलाओं को पूर्व की तरह 50 प्रतिशत रियायत मिलेगी, लेकिन रियायत के लिए न्यूनतम आयु सीमा 2 वर्ष घटा कर 58 वर्ष कर दी गई है । रेल मंत्रालय ने इस नई सुविधा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है *(दै.भा. एवं रा.प., 26.05.11)*

अब हम हुए 121 करोड़

भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है। देश में 62 करोड़ 37 लाख पुरुष और 58 करोड़ 65 लाख महिलाएं हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में पूरे देश में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या में उत्साहजनक वृद्धि हुई है। देश में अब 74 फीसदी लोग पढ़े-लिखे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आना शुरू हो गया है।

राजस्थान में 2001 में कुल आबादी 5 करोड़ 65 लाख थी वह अब बढ़कर 6 करोड़ 86 लाख हो गई है। इसमें 3 करोड़ 56 लाख पुरुष और 3 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं।

(दै.भा.एवं रा.प., 01.04.11)

अब दसवीं तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा

आठवीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद केन्द्र सरकार अब दसवीं कक्षा तक इसका विस्तार करेगी। कैब की 58वीं बैठक के बाद केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने इस आशय की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से सहमति जाता दी है। अगले तीन माह में इसके लिए कैब कमेटी प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करेगी, साथ ही निजी स्कूलों के लिए विकास शुल्क व अन्य सहायता राशि की आड़ में ली जा रही मनमानी वसूली पर भी लगाम कसी जाएगी इसके लिए भी कानूनी मसौदा तैयार किया जा रहा है।

(रा.प., 08.06.11)

मरीजों को निःशुल्क दवाइयां

प्रदेश में गांधी जयंती से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र डिस्पेंसरी से लेकर राज्य के सभी अन्य राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएगी , चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों।

उन्होंने बताया कि मरीजों को जेनरिक दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। जेनरिक दवाइयां भी वही कम्पनियां बनाती है जो ब्राण्डेड दवाइयों का निर्माण करती है। इसके अलावा ऑपरेशन में काम आने वाली सामग्री का खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इस बारे में जल्द ही दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

(न.दु., 28.04.11 एवं रा.प., 07.05.11)

गरीब परिवारों को मिलेंगे मकान

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की जानकारी देते हुए कहा है इस योजना के तहत सरकार राज्य के 10 लाख गरीब परिवारों को मकान बना कर देगी। उन्हें इसके लिए कोई कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। इस योजना पर अगले तीन साल में 3400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने हुडको से कर्ज लिया है।

योजना के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 2 लाख 80 हजार मकान बनाने का लक्ष्य है जिस पर 1400 करोड़ रुपए खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि नरेगा ने गरीब किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है।

(दै.भा., 26.04.11 एवं 01.06.11)

भारत में भूखों की संख्या बढ़ी

भारत में 1990 से 2005 के दौरान भूखे लोगों की संख्या साढ़े छह करोड़ बढ़ गई है। यह संख्या फ्रांस की जनसंख्या से भी ज्यादा है। चैरिटी संस्था ऑक्सफैम ने अपनी 'ग्रोइंग अ बेटर फ्यूचर' नामक एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ग्रामीण गरीबों को आर्थिक विकास से परे रखा गया और कल्याणकारी कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंचे।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अवधि में अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई, लेकिन भूखे लोगों की संख्या बढ़ गई। इसकी वजह खाद्यान्न की मांग का उत्पादन से अधिक होना है और जलवायु परिवर्तन ने इस समस्या को और गंभीर बनाया है।

(दै.भा., 01.06.11)

'कट्स' को क्रेडिबिलिटी अलायंस की मान्यता

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स इन्टरनेशनल) को क्रेडिबिलिटी अलायंस की ओर से पांच साल के लिए मान्यता दी गई है। स्वैच्छिक संगठनों के संघ क्रेडिबिलिटी अलायंस की ओर से यह मान्यता कट्स के अच्छे प्रयासों, नियमों, जवाबदेही तथा पारदर्शिता के उच्च मानदंडों के आधार पर दी गई है।

कट्स इन्टरनेशनल अन्तरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसकी शाखाएं देश में जयपुर, चित्तौड़गढ़, नई दिल्ली व कोलकाता में स्थित हैं। इसके अलावा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी अन्य शाखाएं लुकासा (जाम्बिया), नैरोबी (केन्या), हेनाई (वियतनाम) तथा जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में हैं। यह अनुसंधान, पैरवी तथा नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापार, विनियामक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर कार्य करती है।

पवन ऊर्जा विकास में राज्य अव्वल

चैन्नई में आयोजित विण्ड इण्डिया-2011 अवार्ड समारोह में पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए राजस्थान को अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर के लिए देश के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के निदेशक (तकनीकी) एम. एम. विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 350 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई थीं, जो वर्ष 2008-09 में स्थापित 200 मेगावॉट क्षमता से 75 फीसदी अधिक हैं।

वर्ष 2010-11 में राज्य बजट में सरकार ने 300 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं स्थापित करने की घोषणाएं की थी, जिसकी तुलना में 437 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं राज्य में स्थापित की गई हैं। इन परियोजनाओं की स्थापना पर 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ है। राज्य में अब तक 1521 मेगावॉट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है।

(रा.प., 09.04.11)

नहीं बदले खराब बिजली मीटर

जयपुर बिजली वितरण कंपनी में सिंगल और थ्री फेज मीटर की किल्लत दूर नहीं हो रही। दीपावली के बाद से ही बिजली मीटरों की क्वालिटी को लेकर बिजली कंपनी और मीटर निर्माता कंपनियों में विवाद चल रहा है।

मीटर नहीं होंने की वजह से बिजली के जहां हजारों कनेक्शन बकाया है, वहीं खराब बिजली के मीटर भी नहीं बदले जा रहे। इससे उपभोक्ताओं से औसत के आधार पर मनमानी राशि वसूली जा रही है। मसलन, जगतपुरा निवासी रमाकांत का कहना है कि बिजली कंपनी चार महीने से खराब मीटर को नहीं बदल रही है और पिछली गर्मियों के अनुसार औसत बिल थमा कर पैसा वसूल रही है। जबकि अब सर्दियों के कारण बिजली उपभोग आधे से भी कम रह गया है।

(दै.भा., 15.05.11)

सुनियोजित उपभोग से ऊर्जा की बचत

ऊर्जा के उपलब्ध संसाधनों का यदि सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए तो इससे 30 से 40 फीसदी तक की ऊर्जा की बचत संभव हो सकती है। यह विचार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी के उप महानिदेशक कपिल मोहन ने ऊर्जा का दक्ष उपयोग कर ऊर्जा बचत किए जाने के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय मिशन के तहत उदयपुर में आयोजित कार्यशाला में व्यक्त किए।

उन्होंने बताया कि ऊर्जा के दक्ष उपयोग और ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे है, जिनमें स्टार रेटेड उत्पादों का उपयोग, बचत लेंप योजना, कृषि क्षेत्र में स्टार रेटेड पंपों का उपयोग कर ऊर्जा की बचत की जा सकती है।

(न.ज्यो., 11.05.11)

'समाधान' देगा उपभोक्ताओं को राहत

जयपुर विद्युत वितरण निगम में शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए 'समाधान' नाम से नई व्यवस्था लागू की गई है। समाधान नाम के सॉफ्टवेयर से विद्युत शिकायतें सम्बन्धित अधिकारियों तक ऑनलाइन पहुंचेगी और उन्हें सात दिन में कार्रवाई कर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय पर भेजनी होगी।

निगम अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक सुधांश पन्त ने इसके लिए सचिव प्रशासन पवन कुमार जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी विद्युत संबंधी शिकायतों को सीएमडी के निर्देशानुसार सॉफ्टवेयर में दर्ज करेंगे और उसके दस्तावेजों को स्केन कराकर सम्बन्धित अधिकारी को ई-मेल से भिजवाएंगे।

प्रकरणों पर सात दिन में कार्रवाई करनी होगी। जिसकी रिपोर्ट वे वापस नोडल अधिकारी को भेजेंगे।

(रा.प., 19.06.11)

सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी

राज्य में बढ़ते सौर ऊर्जा उत्पादन को और अधिक गति देने के लिए 2013 तक इस क्षेत्र में करीब 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब तक प्रदेश की 600 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को केन्द्र की मंजूरी मिल चुकी है। अगले दो सालों में इसे 1500 मेगावॉट क्षमता तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

ऊर्जा मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य के जैसलमेर, बाड़मेर, और जोधपुर में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में स्थापित होने वाले कोयला आधारित ताप बिजलीघर परियोजना से प्रदेश को कम से कम 50 प्रतिशत बिजली प्राप्त हो सकेगी। इससे आदिवासी बहुल क्षेत्र के विकास और रोजगार की संभावनाएं भी खुल जाएंगी।

(दै.भा., 28.05.11)

बिजलीघरों के लिए कोल ब्लॉक्स मंजूर

राज्य के छबड़ा, सूरतगढ़ और बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल बिजलीघरों के लिए आखिरकार केन्द्र ने छत्तीसगढ़ के परसा पूर्व और काटेबसान में कोल ब्लाक्स को मंजूरी दे दी है। करीब दो साल से पर्यावरणीय मंजूरी के इंतजार में अटके इन कोल ब्लॉक्स से अब दो चरणों में 15-15 साल के लिए कोयला मिलेगा।

हाल ही केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री जयराम रमेश ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में प्रदेश के कोल ब्लॉक्स को पर्यावरणीय मंजूरी की घोषणा की। इस अहम फैसले से प्रदेश में 15 हजार करोड़ के निवेश की राह खुली है। यह कोयला राज्य के छह सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स के काम आएगा। इनसे 8000 मेगावाट बिजली बनेगी। ये अगले चार-पांच साल में शुरू होंगे और इसके बाद राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता दुगुनी हो जाएगी।

(रा.प. एवं दै.भा., 25.06.11)

मीटर से छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तारी

बिजली मीटर से छेड़खानी कर बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस अनुसंधान में मीटर से छेड़खानी और बिजली चोरी का आरोप सिद्ध होते ही दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। न्यायालय द्वारा ही मीटर व बिजली चोरी की दायित्व राशि तय की जाएगी।

हाल ही तीनों डिस्कॉम के लिए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए आदेशों के तहत किसी भी दोषी व्यक्ति से सीधे बतौर दायित्व राशि व जुर्माना नहीं वसूला जाएगा। दोषी व्यक्ति की पहले गिरफ्तारी होगी और उसका चालान न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके बाद न्यायालय ही दायित्व राशि व जुर्माना तय करेगा।

(रा.प., 15.06.11)

बिजली छीजत, बिजली चोरी ! उपभोक्ता पर है दोनों भारी !!

होगा पानी की हर बूंद का हिसाब

चार महीने से जिस वाटर ऑडिट को लेकर जलदाय विभाग के अभियंता टालमटोल की प्रवृत्ति अपनाए हुए थे, उन्हें अब यह काम एक महीने में पूरा करना होगा। यह ऑडिट पहले केवल जयपुर में होनी थी, लेकिन अब अजमेर, पाली, और भीलवाड़ा में भी करनी होगी।

जल संसाधन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रामलुभाया ने वाटर ऑडिट की समीक्षा बैठक में जलदाय विभाग को यह निर्देश जारी किए। अब इन शहरों में अभियंताओं को पानी की हर बूंद का हिसाब देना होगा। वाटर ऑडिट के तहत शहरों में सप्लाई होने वाले पानी और जनता तक पंहुच रहे पानी के अंतर के कारणों का पता लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पानी पहले से ही बहुत कम है। ऐसे में लीकेज के कारण सप्लाई किया पानी भी जनता तक नहीं पहुंच रहा। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में पानी का 40 प्रतिशत हिंस्सा वर्तमान में लीकेज में जा रहा है।

(रा.प., 12.06.11)

लागू हो नदियों को जोड़ने की योजना

योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया के साथ राज्य की पानी की स्थिति पर हुई चर्चा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार को राज्य में जल की उपलब्धता और मांग के बीच बढ़ती खाई पर विचार करना चाहिए। प्रदेश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने के लिए 50 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसें केन्द्र व योजना आयोग के सहयोग से पूरा किया जा सकता है।

इसके अलावा गहलोत ने नदियों को जोड़ने की योजना को लागू करने की वकालत करते हुए राजस्थान की शारदा यमुना-साबरमती लिंक परियोजना को भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने की मांग की है।

(रा.प.एवं दै.भा., 28.06.11)

गांवों में नहीं मिल रहा पीने का पानी

प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भूजल स्तर नीचे जाने के कारण कई जिलों के नगरीय व दूर-दराज के गांवों के हजारों हैंडपम्प और ट्यूबवैल नकारा हो चुके हैं। इससे लोगों को पानी की किल्लत का भारी सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में तो टैंकरों से भी पानी सप्लाई नहीं हो रहा। वहां लोग एक घड़े पानी के लिए भी तरस रहे हैं।

अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र के गांव महाराजावास व रिवाली में सभी हैंडपम्प सूखे पड़े हैं। सरकार ने पूरी बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र को डार्क जोन घोषित किया हुआ है। इससे नए नलकूपों की खुदाई पर भी रोक है। पहुंच वाले लोगों ने अवैध रूप से बोरिंग खुदवा रखे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।

(रा.प., 09.05.11)

जलमणि योजना में बनेंगे टांके

प्रदेश के 300 और उससे अधिक बच्चों की क्षमता वाले स्कूलों के लिए जलमणि योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रदेश में 1800 स्कूलों में टांके बनाए जा सकेंगे। इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए भरा जाएगा। टांके में भरा वर्षा जल बच्चों के पीने के पानी के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।

केन्द्र सरकार के राजीव गांधी पेयजल मिशन के तहत इस योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में केन्द्र सरकार ने 40 हजार रुपए प्रति स्कूल देने की स्वीकृति दी है, जबकि एक टांका बनाने में करीब एक लाख रुपए का खर्च आने की संभावना है। बाकी राशि 60 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में इस योजना पर जल्दी ही काम शुरू होने की संभावना है। *(दै.भा., 07.05.11)*

बारिश का पानी सहेजने पर खास जोर

राज्य सरकार प्रदेश में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए वर्षा जल पुनर्भरण पर विशेष जोर देने जा रही है। योजना के तहत पांच शहरों में सूख चुके ट्यूबवैल और हैण्डपम्पों के पास ढांचे बना कर भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा। साथ ही इन शहरों में जलदाय विभाग के सभी दफ्तरों में ऐसे ढांचे बनाए जाएंगे।

यह सभी काम 15 जुलाई तक कर लिए जाएंगे। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) एच.के.नारंग ने बताया कि सरकारी स्तर पर इस योजना में जयपुर, अजमेर, पाली, टोंक और ब्यावर को शामिल किया गया है। ट्यूबवैलों व हैण्डपम्पों के पास ढांचे बनाने की विशेष जिम्मेदारी इंजिनियरों को दी गई है। *(दै.भा., 18.04.11)*

फिर शुरू होगी स्वजलधारा योजना

जलदाय विभाग ने दो साल पहले बंद हुई स्वजलधारा और सेक्टर रिफॉर्म योजना को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर ली है। पहले यह योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से आमजन की पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई थी।

योजना के तहत ट्यूबवैल और हैण्डपम्प का निर्माण, पेयजल लाइन बिछाने, पम्प हाउस खोलने जैसे कई काम करवाए जाने थे। इसके लिए ग्रामीण विकास समितियों का गठन किया गया था। लेकिन इन योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ता देख केन्द्र सरकार ने इन्हें बन्द कर दिया था।

पिछले दिनों राज्य सरकार ने बंद पड़ी स्वजलधारा की करीब 527 योजनाओं को फिर से चालू करने का फैसला किया है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए अब पंचायत स्तर पर काम कराए जाएंगे।

(रा.प., 31.05.11)

अगली पीढ़ी के लिए हो सकता है जल संकट

भूजल के अतिदोहन के चलते प्रदेश में भूमिगत जल के स्तर में 93.81 फीसदी क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। 1984 में जहां अतिदोहित श्रेणी के क्षेत्रों की संख्या सिर्फ 12 थी, जो अब बढ़कर 164 हो चुकी है। प्रदेश में पानी का आकलन के लिए 237 ब्लॉक है। जनसंख्या विस्तार के साथ कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ने के कारण भी पानी का दोहन बढ़ा है।

वर्तमान में प्रदेश के 237 ब्लॉक में 164 ब्लॉक अति दोहित, 34 विषम, 8 अर्द्ध विषम और 30 ब्लॉक सुरक्षित हैं। लगातार दोहन से सुरक्षित क्षेत्रों में भी भूजल स्तर में गिरावट आने लगी है। सरकार की ओर से अभी तक पानी के अतिदोहन को रोकने का जहां कोई प्रयास नहीं है वहीं भूजल के रीचार्ज का काम भी नहीं हो रहा। इससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जल संकट गंभीर समस्या बन सकता है। *(दै.भा., 05.06.11)*

महिला साक्षरता में पिछड़ा राजस्थान

राज्य सरकार ने पिछले दस सालों में महिला साक्षरता बढ़ाने के नाम पर 7 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बावजूद इस अवधि में महिला साक्षरता में केवल पौने नौ फीसदी ही इजाफा हुआ है। जबकि बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में महिला शिक्षा का स्तर इस अवधि में क्रमशः 20 व 17 फीसदी बढ़ा है। यह राजस्थान की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है।

यह ही नहीं, महिला शिक्षा के मामले में राज्य पूरे देश में भी फिसड्डी है। राज्य में जनगणना 2011 के नतीजों ने सरकारी कागजी दावों की पोल खोलते हुए इस सच्चाई को उजागर किया है। प्रदेश में इतना भारी भरकम खर्च करने के बावजूद महिला शिक्षा में खास इजाफा नहीं होना कई सवाल खडे करता है। *(दै.भा. एवं रा.प., 06.04.11)*

विधवा शिक्षिकाओं को मिलेगी छूट

शिक्षक के पदों पर नियुक्त विधवाओं और परित्यक्ताओं को अब बीएड और बीएसटीसी करने की तीन साल की बाध्दता हटा दी गई है। पहले नियुक्ति के तीन साल की अवधि में यह कोर्स करना जरूरी था। राज्य सरकार ने इसके लिए राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम 2011 जारी कर दिए हैं। हालांकि अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक पद पर नियुक्त विधवाओं और परित्यक्ताओं को बीएसटीसी या बीएड करने की तिथि से ही नियमित माना जाएगा।

राज्य सरकार ने नियुक्त महिलाओं को बीएसटीसी या बीएड करने के लिए अध्ययन अवकाश मंजूर करने के लिए नए नियमों के तहत पात्र बनाया है। ये नियम उन विधवा और परित्यक्तताओं पर लागू होंगे जिन्हें बीएसटीसी या बीएड करने की पात्रता के मापदंडों पर छूट देकर नियुक्ति दी गई है।

(दै.भा., 01.06.11)

राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम शुरू

हाल ही यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हरियाणा के मेवात जिले के माड़ीखेड़ा गांव से 'राष्ट्रीय जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम' की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को अब सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान मुफ्त इलाज मिलेगा। जिसमें मुफ्त प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन, दवाएं, उपयोग की वस्तुएं, जांच, भोजन, रक्त सुविधा घर से सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र तक मुफ्त वाहन आदि सम्मिलित हैं।

इसके अलावा उनके शिशु की देखभाल का जिम्मा भी 30 दिन तक केन्द्र सरकार उठाएगी। जिसमें उपचार, दवाएं, उपयोग की वस्तुएं, जांच आदि सभी सुविधाएं भी मुफ्त प्रदान की जाएगी। यह योजना ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत लागू होगी। कार्यक्रम में देश भर में तैनात 8 लाख आशा कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग दिया जाएगा। केन्द्र सरकार की इस योजना पर प्रति वर्ष करीब 23 हजार करोड़ रुपया खर्च होगा। *(रा.प. एवं दै.भा., 02.06.11)*

सशक्त होंगे स्वयं सहायता समूह

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत देश के सात करोड़ गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूह गठित किए जाएंगे। जिला स्तर पर इनका फेडरेशन बना कर स्वरोजगार के अवसर मुहैया किए जाएंगे।

यूपीए और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बांसवाड़ा जन सभा में यह घोषणा करते हुए कहा कि यह योजना पहले प्रदेश के 16 जिलों में लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को अधिक आर्थिक सहायता देने के लिए जल्द एक संस्था गठित की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। गरीबी से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित इस मिशन की सफलता महिलाओं के हाथ में होगी। उन्होंने अन्य योजनाओं की सफलता का भी जिम्मा महिलाओं पर डालते हुए कहा कि महिलाएं सामाजिक अंकेक्षण और सूचना के अधिकार का सहारा लेकर योजनाओं को कामयाब बनाएं।

(रा.प. एवं दै.भा., 04.06.11)

आंगनबाडी-अभी सरकारी नौकरी से दूर

केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन दोगुना करने की घोषणा की थी। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मासिक मेहनताना 3000 रुपए तथा आंगनबाडी सहायक का मानदेय 1500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तमंत्री की इस पहल से देश भर की करीब 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को लाभ मिलेगा।

आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और सहायकों द्वारा काफी लंबे अर्से से उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारी किए जाने की मांग चल रही है। जिस पर वित्त मंत्री ने अभी भी ध्यान नहीं दिया है। *(रा.प. 23.05.11)*

महिला आयोग -कौन करे सुनवाई

राज्य महिला आयोग में पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक भी जिम्मेदार व्यक्ति नही हैं। क्योंकि, वहां अध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद करीब दो साल से खाली पड़े हैं। हालात यह है कि महिला उत्पीड़न से जुड़े डेढ़ हजार से भी ज्यादा प्रकरण पिछले दो साल से लंबित हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही।

यह एक शर्मनाक स्थिति है कि राज्य के किसी भी जिले में महिला अत्याचारों के मामलों की सुनवाई नहीं हो रही। आयोग की सचिव द्रोपदी मलिक का कहना है कि खाली पद भरे जाएंगे तभी जाकर जनसुनवाई हो सकेगी। पद खाली होने से हैल्प लाइन का भी काम अटका हुआ है। *(दै.भा. 07.04.11)*

महिलाएं एक साथ करें सफर तो फायदा

रोडवेज बसों में यदि पांच महिलाएं एक साथ सफर करें तो उन्हें 25 फीसदी रियायत मिलेगी। यह छूट अप्रेल से लागू हो गई है। महिलाओं द्वारा समूह में यात्रा के लिए आरक्षण चाहने पर सीट आरक्षण की व्यवस्था भी है।

राज्य सरकार का मानना है कि रोडवेज बसों में रोजाना हजारों महिलाएं सरकारी या निजी नौकरी अथवा दैनिक मजदूरी आदि के लिए जाने-आने के लिए रोडवेज बसों में यात्रा करती हैं। समूह में यात्रा करने पर इन्हें द्रुतगामी और साधारण बसों के यात्री किराए में 25 फीसदी रियायत मिलेगी। यह सुविधा राज्य में संचालित बसों में ही मिलेगी। *(रा.प., 04.04.11)*

कन्या भ्रूण हत्या पर लगेगी लगाम

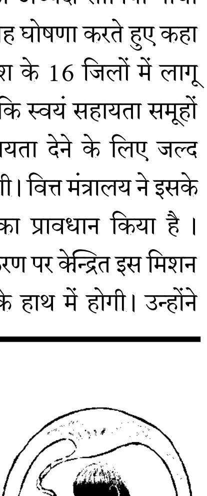

चिकित्सा विभाग की बेरुखी के चलते बालिका भ्रूण हत्या और घटता लिंगानुपात का कलंक राजस्थान के माथे पर लगा है। सामने आया है कि विभाग ने सोनोग्राफी केन्द्रों पर फार्म-एफ को सही तरीके से भरने और उन पर निगरानी के ठोस प्रयास ही नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि सोनोग्राफी केन्द्र बेखौफ होकर भ्रूण हत्याएं करते रहे। प्रदेश में लिंगानुपात में आई कमी इस बात को खुलासा करती है।

यह तथ्य उजागर होने के बाद अब जाकर चिकित्सा विभाग चेता है। विभाग कन्या भ्रूण हत्या व लिंग परीक्षण पर लगाम लगाने के मकसद से प्रदेश में निगरानी रखने के लिए चार निरीक्षक दल गठित कर दिए हैं। इन दलों को कार्रवाई के तमाम सबूतों को पुष्ट करने के लिए खुफिया कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर जैसे उपकरणों से लैस किया जाएगा। इसके अलावा जो मुखबिर लिंग परीक्षण की सही सूचना देगा उसे 5 हजार रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। *(रा.प., 05.05.11 एवं 27.05.11)*

सड़क सुरक्षा

रोज बहता है सड़कों पर खून और उजड़ जाते हैं 25 परिवार

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसी का सुहाग उजड़ रहा है तो किसी घर का चिराग बुझ रहा है। लेकिन इसके बावजूद न लोग सुधरने को तैयार है और न ही वाहन चालक। जनवरी 2009 से फरवरी 2011 तक हुए हादसों के आंकड़े बताते हैं कि इन 780 दिनों में हर दिन 68 हादसे पुलिस दर्ज करती रही। इन हादसों में 112 लोग हताहत होते रहे और इनमें से 25 लोगों की प्रतिदिन मौत हुई। घायलों में कई ऐसे भी है जो जिंदगी में कभी बिस्तर से नहीं उठ सके। अधिकांश को कई माह अस्पतालों में रहना पड़ा। सरकार की ओर से विधायक ओम बिड़ला को दी गई सूचना में दर्ज आंकड़े यह सच्चाई बयान करते हैं।

राज्य में अंधाधुंध रफ्तार से दौड़ते वाहन, क्षमता से अधिक परिवहन, नकारा वाहनों का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का न होना, राज्य की पुलिस के पास संसाधनों की कमी, सड़कों की दुर्दशा और खतरनाक मोड़ इन दुर्घनाओं की खास वजह है। इसके अलावा सड़क हादसों के लिए बने कानूनी प्रावधान भी पीड़ित को राहत नहीं दिला पाते। *(रा.प., 20.05.11)*

पर्यावरण

'ग्रीन अकाउंटिंग' बताएगी पर्यावरण पर विकास का असर

आर्थिक विकास से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर जारी बहस के बीच केन्द्र सरकार ने 'ग्रीन अकाउंटिंग सिस्टम' विकसित करने का फैसला किया है। इससे यह जाना जा सकेगा कि आर्थिक विकास का पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है। यह व्यवस्था वर्ष 2015 तक अमल में आ जाएगी। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने यह जानकारी देते हुए बताया कि योजना आयोग और पर्यावरण मंत्रालय ने मिलकर जल्द ही ख्यात पर्यावरण अर्थशास्त्री पार्थ दास गुप्ता की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला किया है। इसमें योजना आयोग के सदस्य किरीट पारीख, विजय केलकर और नितिन देसाई जैसे अर्थशास्त्री भी रहेंगे। *(दै.भा., 10.05.11)*

राज्य में रोपे जाएंगे 11 लाख पौधे

राज्य के डूंगरपुर जिले में एक ही दिन में छह लाख पौधों का रोपण कर रिकॉर्ड बनाने वाली राज्य सरकार एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। यह रिकॉर्ड बनाया जाएगा पूरे प्रदेश में एक ही समय पर 11 लाख पौधों का रोपण कर। यह काम किया जाएगा 11 जुलाई, 2011 को राज्य के तमाम प्रारंभिक व माध्यमिक स्तर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं के माध्यम से। राज्य सरकार ने इसकी तैयारी के लिए राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के स्टेट चीफ कमीश्नर निरंजन आर्य को निर्देश दिए हैं। श्री आर्य ने इसके लिए परिपत्र जारी कर विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को 11 बजे एक साथ पूरे राज्य में हरित राजस्थान योजना के तहत 11 लाख पौधे लगाने के लिए 'पर्यावरण चेतना परियोजना 'गो-ग्रीन' के संचालन की जिम्मेदारी प्रदेश स्काउट गाइड संगठन को सौंपी है। इनमें सर्वाधिक 66 हजार पौधे पाली जिले में लगाए जाएंगे। *(दै.भा., 12.06.11)*

दूरसंचार सेवाएं

नहीं चलेगा चोरी गया मोबाइल

आने वाले दिनों में आपका मोबाइल चोरी होने पर चालू ही नहीं हो पाएगा। फोन के ईएमईआई(इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेन्टिफिकेशन) नंबर के आधार पर चोरी के मोबाइल किसी भी नए नंबर पर नहीं चल पाएंगे। प्रारंभिक चर्चा के बाद दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह की सुविधा के लिए उपयोग होने वाली तकनीकों को खंगालना शुरू कर दिया है।

ट्राई के सदस्य सुधीर गुप्ता ने बताया कि इस बारे में ऑपरेटरों से चर्चा की गई थी। उनसे मिले सुझावों और विचारों के आधार पर आगे कार्य किया जा रहा है। गुप्ता के मुताबिक, इस समय ब्रिटेन सहित कुछ अन्य पश्चिम देशों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। इस तकनीक के तहत एक ऐसा सर्वर बनाया जाएगा जहां सभी आपरेटर अपने ग्राहक को सिम कार्ड देते वक्त उनके मोबाइल के ईएमईआई नंबर भी डाल देंगे। *(दै.भा., 14.06.11)*

निवेशक शिक्षा

बढ़ेगी निवेशक जागरूकता

निवेशक सुरक्षा एवं सुरक्षा निधि (फंड) का गठन निवेशकों में जागरूकता का प्रसार करने व उनके हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है। वर्ष 2007 में स्थापित किए गए इस फंड का वित्तीय वर्ष 2009-10 में आकार लगभग 50 करोड़ रुपए था। इन फंड का प्रबंधन शेयर बाजार नियामक ऐजेंसी (सेबी) करती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में निवेशक जागरूकता का स्तर बहुत कम है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि 120 करोड़ की जनसंख्या में से मात्र एक करोड़ 80 लाख लोगों के ही डीमेट खाते हैं। इसके मायने यह है कि देश की मात्र 1.5 प्रतिशत जनसंख्या को ही बुनियादी निवेशक जानकारी उपलब्ध है।

ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि सेबी को उक्त फंड में उपलब्ध पूंजी का तेजी से उपयोग करना चाहिए, जिससे लोग बड़े स्तर पर जागरूक हो सकें। इससे निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी और बेईमानी पर भी अंकुश लग सकेगा। उल्लेखनीय है कि फंड के नियमों के तहत निवेशक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा कार्यक्रम, सेमीनार व संगोष्ठियों का आयोजन करने के लिए सेबी को स्वतंत्रता दी गई है। *(न.दु., 01.06.11)*

वित्तीय सेवाएं

एटीएम में फंसा पैसा 7 दिन में लौटाना होगा

बैंकों के एटीएम में पैसा फंसने से परेशान लोगों को जल्द ही इस समस्या से निजात मिलने वाली है। रिजर्व बैंक ने एटीएम में फंसी राशि को सात दिन में लौटाने का निर्देश देते हुए कहा हैं कि ऐसा नहीं होने पर उन्हें ग्राहक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। रिजर्व बैंक का यह नया निर्देश एक जुलाई 2011 से लागू होगा। यह सामने आया है कि कई बार बैंकों के एटीएम से पैसा निकलता नहीं है, पर ग्राहक के खाते से राशि कट जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के इस नए निर्देश से ग्राहकों को अब इस समस्या के निजात के लिए बैंकों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

केन्द्रीय बैंक की इस बारे में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ग्राहक की शिकायत मिलने के दिन से पैसा लौटाने की समयसीमा 12 कार्यदिवसों से घटा कर अब 7 कार्यदिवस कर दी गई है। ग्राहक को इस तरह की शिकायत होने के 30 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करनी होगी। तभी वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। *(रा.प., 28.05.11)*

उपभोक्ता फैसले

बिना वजह पेयजल कनेक्शन काटा

टोंक रोड स्थित वसुंधरा कॉलोनी निवासी कालूराम ब्याडवाल ने जलदाय विभाग के खिलाफ उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने मंच को बताया कि वह समय पर पानी के बिल का भुगतान करते रहे हैं। उन पर कोई बकाया राशि नहीं होने के बावजूद बिना किसी सूचना के 4 मई, 2008 को जलदाय विभाग ने उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो जलदाय विभाग के अधिकारियों ने गलती से कनेक्शन काटना बताया। लेकिन बार-बार विभाग में चक्कर लगाने के बावजूद अभी तक उनका पेयजल कनेक्शन नहीं जोड़ा गया।

मामले की सुनवाई पर मंच ने माना कि जलदाय विभाग ने पानी का कनेक्शन नहीं जोड़ कर सेवा दोष किया है। इससे उपभोक्ता को तीन साल तक बिना किसी कारण के सरकारी पेयजल सेवाओं से वंचित रहना पड़ा। मंच ने जलदाय विभाग को आदेश दिया कि वह एक महीने में कालूराम का जल कनेक्शन वापस जोड़े । साथ ही मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति स्वरूप उन्हें एक लाख रुपया भी दे। मंच ने इसमें से पचास हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में देने को कहा है । मंच ने परिवाद व्यय के तौर पर कालूराम को 3000 रुपए भी दिलवाए।

(रा.प., 27.04.11)

हॉस्पिटल को भारी पड़ी लापरवाही

महारानी फार्म दुर्गापुरा निवासी विकास आर्य ने दुर्लभजी हॉस्पिटल के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर में परिवाद दर्ज कराया। उनके वकील ने आयोग के सामने उनका पक्ष रखते हुए बताया कि विकास अपनी पत्नी को प्रसव काल के दौरान 29 अक्टूबर, 2001 को दिखाने के लिए दुर्लभजी लाए थे। उन्होंने वहां मौजूद डॉक्टर से उनकी सोनोग्राफी करने के लिए कहा तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया और हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया।

उनकी पत्नी का प्रसव बिना आपरेशन हुआ। लेकिन इस दौरान डॉक्टर और हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरती गई , जिससे उनकी पत्नी व बच्चे की सही देखभाल नहीं हुई। फलस्वरूप पत्नी व बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया।बच्चा जीवन पर्यन्त दूसरों पर आश्रित हो गया है। ऐसे में उन्होंने हास्पिटल से मुआवजा दिलाने की मांग की।

मामले की सुनवाई के दौरान हॉस्पिटल ने इन आरोपों को गलत बताया। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने और केस रिकॉर्ड देखने के बाद हास्पिटल को लापरवाही बरतने का दोषी माना। आयोग ने दुर्लभजी हॉस्पिटल को 3 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा व 20 हजार रुपए परिवाद खर्च के रूप में चुकाने का आदेश दिया है।

(दै.भा. एवं रा.प., 15.06.11)

बिना रसीद रोडवेज ने वसूला लगेज शुल्क

रोडवेज की जयपुर-दिल्ली डीलक्स बस से जी.एल.अग्रवाल ने अक्टूबर, 2008 में यात्रा की थी। उनसे बस की डिक्की में सामान रखने के लिए बस परिचालक ने प्रति नग दो रुपए शुल्क मांगा। उन्होंने मांगा गया शुल्क परिचालक को दे दिया, लेकिन उन्हें इसकी रसीद नहीं दी गई। उन्होंने बुकिंग क्लर्क से बात की तो जवाब मिला 1995 से 2 रुपए प्रति नग लेने के आदेश हैं , जिसकी रसीद भी मिलती है।

उन्होंने दिल्ली उपभोक्ता मंच में रोडवेज के खिलाफ परिवाद दायर कर पूरी स्थिति बताई। सुनवाई पर रोडवेज की ओर से यह नहीं बताया जा सका कि 15 साल पहले जारी उक्त आदेश से आज तक कितना लगेज शुल्क जमा हुआ। उपभोक्ता मंच ने यह भी पाया कि रोडवेज द्वारा काटे गए टिकट पर यात्रा के पूरे विवरण के साथ किराया राशि का इंद्राज नहीं था।

उपभोक्ता मंच ने इन अनियमिताओं को गंभीर मानते हुए रोडवेज को आदेश दिया है कि वह एक लाख रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में हर्जाने स्वरूप जमा कराए। साथ ही, परिवादी जी.एल. अग्रवाल को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 हजार रुपए अदा करने के निर्देश भी दिए हैं।

खास समाचार

भ्रामक विज्ञापन रोकने की कवायद

भारत सरकार की ओर से खाद्य उत्पादों के भ्रामक विज्ञापन रोकने की कवायद की जा रही है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री के.वी.थामस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हम इसके लिए सबसे पहले एक समिति का गठन करने जा रहे हैं , यह समिति इस बात को सुझाएगी कि भ्रामक विज्ञापनों को कैसे रोका जाए।

उनका कहना है कि रोजाना इस तरह की शिकायतें मिलती है कि खाद्य उत्पादों के उत्पादक या विक्रेता भ्रामक विज्ञापन के जरिये उपभोक्ताओं का नाजायज फायदा उठाते हैं या उन्हें भ्रमित करते हैं। उनका कहना था कि बात केवल खाद्य उत्पादों की ही नहीं बल्कि सभी उत्पादों के उपभोक्ताओं की है, जिसमें रियल एस्टेट , सोना-चांदी, दवाएं, कपड़े आदि उत्पाद भी शामिल हैं।

(न.नु., 04.06.11)

पूरे महीने खुलेंगी राशन की दुकानें

प्रदेश में राशन की सभी 23 हजार दुकानों पर अब पूरे महीने राशन मिलेगा। राशन की दुकानों को साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर किसी भी दिन बंद नहीं रखा जा सकेगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन जिला कलेक्टर निर्धारित करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने यह नई व्यवस्था लागू की है।

राशन की दुकानों के खुलने का समय एक अप्रेल से 30 सितम्बर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा एक अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक का रहेगा।

(दै.भा., 07.04.11)

उपभोक्ताओं की समस्या निवारण हेतु हैल्पलाइन

भारत सरकार के उपभोक्ता मामलात मंत्रालय ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए 2005 में दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाइन शुरू की थी। जिसका टोल फ्री नंबर 1800114000 है। इसकी सफलता को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य स्तर पर भी ऐसी उपभोक्ता हैल्पलाइन शुरू करने का निर्णय लिया। इस कड़ी में राजस्थान सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने भी राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन संचालित करने का निर्णय लिया और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2011 को राज्यस्तरीय उपभोक्ता हैल्प लाइन का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।

राज्य उपभोक्ता हैल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 18001806030 है । आम उपभोक्ता अपनी समस्याओं के निवारण के लिए राजकीय कार्यालय समय में अवकाशों को छोड़कर प्रातः 9.30 बजे से सायंकाल 6.00 तक टोल फ्री नंबर 18001806030 पर सम्पर्क कर इस सुविधा का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।

स्त्रोत: रा. प.: राजस्थान पत्रिका, दै. भा.: दैनिक भास्कर, न. नु.: नफा नुकसान, दै. न.: दैनिक नवज्योति

पाँचवा-स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259 फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई-मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्रा. लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।